

प्रकाशन का 107 वाँ वर्ष

आज

3 रूपये मात्र



लखनऊ, मंगलवार 3 नवम्बर, 2026 | Online Edition : www.ajhindidaily.com | नगर संस्करण पृष्ठ-12 | मूल्य 3.00 रुपये

वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, (मध्य प्रदेश संस्करण), कानपुर, (झांसी संस्करण), लखनऊ , आगरा, बरेली, पटना, रांची, (धनबाद संस्करण) तथा जमशेदपुर से प्रकाशित

आंगनबाड़ी कर्मियों को फोन के साथ कैशलेस इलाज भी

योगी सरकार ने दिवाली से पहले दिया लाखों परिवारों को उपहार



लखनऊ (आससे.)। इस बार प्रदेश की लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की दिवाली पहले से अधिक खुशियों के साथ मनेगी। योगी सरकार ने त्योहार से पहले उनके मानदेय में बढ़ोतरी कर लाखों परिवारों को उपहार दिया है। लंबे समय से बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा की जिम्मेदारी निभा रहीं इन कर्मियों को अब बढ़ा हुआ मानदेय मिल रहा है। कार्यकर्ताओं का मानदेय 8 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये और सहायिकाओं का 4 हजार से बढ़ाकर 6 हजार रुपये प्रतिमाह किया गया है। इससे कार्यकर्ताओं को हर महीने 4 हजार और सहायिकाओं को 2 हजार रुपये अतिरिक्त मिल रहे। बढ़ी हुई आमदनी से जहां घर का बजट मजबूत होगा, वहीं त्योहार की तैयारियों में भी आसानी होगी। योगी सरकार ने करीब 3.35 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं व परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी है। अब उन्हें अपने परिवार के साथ हर साल 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज का प्रावधान है। सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में जरूरत होने पर इसका लाभ ले सकती हैं। इसके अलावा अब तक मिलने वाली दो साड़ियों के स्थान पर तीन साड़ियां दी जाएंगी। इसके लिए 500 रुपये अतिरिक्त उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। इस पर सरकार करीब 20 करोड़ रुपये खर्च कर रही है।

राहुल ने प्रधानमंत्री को दी बहस की चुनौती



कहां-मैं जानता हूं आप डरते हो, विदेशी मदद से प्रधानमंत्री बनने से लगाया आरोप

नयी दिल्ली (आससे.)। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी पर विदेशी मदद के सहारे सत्ता में बने रहने का आरोप लगाकर राजनीतिक विवाद तेज कर दिया। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी विदेशी मदद से प्रधानमंत्री बने और अब भी इसी मदद के सहारे इस पद पर बने हुए हैं। उन्होंने देश की आर्थिक व्यवस्था और विदेशी सोशल मीडिया को लेकर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को खुली बहस की चुनौती देते हुए कहा कि वह किसी भी मंच पर और किसी भी समय उनसे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री इसलिए बहस के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि राहुल उनके बारे में क्या जानते हैं।राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने लिखा, मोदी जी, इस देश से झूठ बोलना बंद कीजिए। आप विदेशी मदद से प्रधानमंत्री बने और विदेशी मदद से ही प्रधानमंत्री बने हुए हैं। राहुल ने आगे आरोप लगाया कि देश की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह विदेशियों के नियंत्रण और समर्थन में है। उन्होंने यह भी दावा किया कि विदेशी सोशल मीडिया पूरी तरह प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है।

सौर ऊर्जा से मजबूत हो रही देश की ऊर्जा सुरक्षा, रोजगार के नये अवसर भी बनेंगे-मोदी

नयी दिल्ली (आससे.)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बदलाव तेजी से हो रहा है और देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सौर ऊर्जा की भूमिका लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार न केवल बिजली का खर्च कम करने में मदद कर रहा है, बल्कि रोजगार के नए अवसर पैदा करने और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी और ब्लूमबर्ग एलपी के संस्थापक माइकल आर. ब्लूमबर्ग द्वारा लिखे गए एक लेख को साझा करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि लेख में नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार, रूफटॉप सोलर, ऊर्जा भंडारण और बिजली पारेषण के क्षेत्र में निवेश की बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया गया है। मोदी ने केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी का एक अन्य लेख भी साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत की सौर ऊर्जा यात्रा नए अवसरों के द्वार खोल रही है। लेख में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना और पीएम-कुसुम जैसी पहलों के माध्यम से सौर ऊर्जा के बढ़ते प्रसार का उल्लेख किया गया है। जोशी ने अपने लेख में सौर ऊर्जा से संचालित कृषि, ऊर्जा भंडारण, विनिर्माण और हरित रोजगार जैसे क्षेत्रों में भविष्य की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला है। भारत का लक्ष्य 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है और इस दिशा में सौर ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।



सोनिया गांधी ने लालू से की मुलाकात

नयी दिल्ली (आससे.)। दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। इंडिया ब्लॉक की रामलीला मैदान में हुई रैली के बाद इस मुलाकात को विपक्षी एकजुटता के लिहाज से अहम माना जा रहा है। ऐसे समय में जब विपक्ष मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और वोट चोरी के मुद्दे पर केंद्र सरकार तथा चुनाव आयोग को घेर रहा है।

कांग्रेस ने लगाया आईडीबीआई बैंक की बिक्री में घोटाले का आरोप

नयी दिल्ली (आससे.)। कांग्रेस ने आईडीबीआई बैंक को कनाडा की कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को बेचने की प्रक्रिया में बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए इसे तत्काल रोकने और पूरे मामले की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस के पूर्व सांसद एवं प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने सोमवार को जारी बयान में आरोप लगाया कि भाजपा सरकार मुनाफा कमाने वाले सरकारी बैंक को विदेशी कंपनी के हाथों सौंप रही है। उन्होंने दावा किया कि आईडीबीआई बैंक ने 2021 से 2026 के बीच 30,105 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है। इसके बावजूद सरकार बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचकर उसका नियंत्रण और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का दर्जा समाप्त करने जा रही है। गोहिल के मुताबिक, सरकार और एलआईसी की कुल 62.72 प्रतिशत हिस्सेदारी 52,878 करोड़ रुपये में बेचने की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई। उन्होंने सवाल उठाया कि पहले बैंक का मूल्यांकन 94.42 रुपये प्रति शेयर किया गया था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 75 रुपये कर दिया गया। इसके बाद 81 रुपये प्रति शेयर की दर से बिक्री का फैसला किया गया। उन्होंने दोनों मूल्यांकन रिपोर्ट सार्वजनिक करने और दूसरे बोलीदाता की जानकारी देने की मांग की। गोहिल ने कहा कि 2003 में तत्कालीन वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने संसद में आश्वासन दिया था कि आईडीबीआई बैंक में सरकार की हिस्सेदारी कभी 51 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

जेपीसी से जांच कराने की मांग



शरद पवार अस्पताल में भर्ती



पुणे (एजेंसी)। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के नेता शरद पवार को पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। उन्हें सांस लेने के दौरान सीने में दर्द की शिकायत हुई थी। इसके बाद सामान्य स्वास्थ्य जांच और चिकित्सकीय निगरानी के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया।रूबी हॉल क्लिनिक के मुख्य हृदय रोग विशेषज्ञ, अध्यक्ष और प्रबंध न्यासी डॉ पुरवेज के. ग्रांट ने आधिकारिक बयान जारी किया। उन्होंने कहा, शरद पवार को सीने में दर्द की शिकायत के बाद सामान्य स्वास्थ्य जांच और मेडिकल निगरानी के लिए रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। उम्मीद है कि उनकी स्थिति में सुधार होगा।

ईडी की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट गये आजम



नयी दिल्ली (आससे.)। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जेल से रिहाई के तुरंत बाद ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के मामले में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इसी सप्ताह सुनवाई करने पर सहमति जताई है। सोमवार को अधिवक्ता निजाम पाशा ने सीजेआई सूर्यकांत के समक्ष मामले का उल्लेख किया था। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29 अक्तूबर को दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को जमानत दी थी। अदालत ने आजम खान की 10 साल की सजा पर रोक लगाई थी, लेकिन उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद 31 अक्तूबर को दोनों रामपुर जेल से रिहा हुए। हालांकि, जेल के बाहर मौजूद ईडी की टीम ने आजम खान को हिरासत में ले लिया। ईडी ने यह कार्रवाई मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के अलग मामले में की थी। इसके बाद रविवार को गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत ने आजम खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब उन्होंने ईडी की इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

पंजाब में आप के तीन विधायक भाजपा में शामिल

नयी दिल्ली (आससे.)। पंजाब में आम आदमी पार्टी को झटका देते हुए उसके तीन विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह, हरमीत सिंह पठानमाजरा और चेतन सिंह जौड़ामाजरा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तीनों नेताओं ने सोमवार को नयी दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी के पंजाब प्रभारी सतीश पूनिया की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इससे पहले तीनों विधायकों ने आप की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। कुंवर विजय प्रताप सिंह ने पंजाब विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। अमृतसर नॉर्थ से विधायक और पूर्व आईपीएस अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह लंबे समय से पार्टी नेतृत्व की आलोचना कर रहे थे। जून 2025 में आप ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पांच साल के लिए निलंबित कर दिया था।

अराजकता से सत्ता हासिल करना चाहती है कांग्रेस- अमित शाह

लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा में हुए शामिल

हैदराबाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह लगातार चुनावी हार का सामना करने के बाद अराजकता के जरिये सत्ता हासिल करने और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यहां भाजपा की लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा से पहले एक्स पर एक पोस्ट में यह बात कही। उन्होंने कहा, नागरिकों ने इन हमलों से अपने लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए कमर कस ली है। शाह सोमवार दोपहर को यहां बेगमपेट हवाई अड्डे पहुंचे। वह यहां भाजपा की पदयात्रा में शामिल होने के लिए यहां आए थे। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी और तेलंगाना भाजपा के अन्य नेताओं ने हवाई अड्डे पर शाह का गर्मजोशी से स्वागत किया। पदयात्रा में जनता को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा, आज मैं हैदराबाद की इस पवित्र भूमि पर लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ रैली में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले मां भाग्य लक्ष्मी के चरणों में प्रणाम करता हूं और सरदार पटेल साहब को भी मनपूर्वक नमन कर अपनी बात की शुरुआत करता हूं। उन्होंने कहा, अगर सरदार उस वक्त निजाम को न झुकाते तो हैदराबाद आज भारत का हिस्सा न होता। वो सरदार साहब ही थे, जिन्होंने हैदराबाद के निजाम को झुकाकर हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाया। तेलंगाना को भारत का हिस्सा बनाया।



दिल्ली-एनसीआर में दीपावली पर सिर्फ ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे

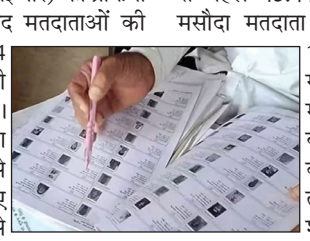
नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में 7 और 8 नवंबर 2026 को ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। पटाखे केवल सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक जलाए जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और अधिसूचित साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर रोक लगाई है।

नौसेना के लिए खरीदे जायेंगे आठ नए आधुनिक युद्धपोत

नयी दिल्ली। आने वाले वक्त में भारतीय नौसेना की ताकत काफी बढ़ने वाली है। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को भारतीय नौसेना के लिए आठ अगली पीढ़ी के कॉर्वेट (युद्धपोत) हासिल करने के वास्ते गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) के साथ 53,866 करोड़ रुपये के करार किए हैं।

एसआईआर के बाद पांच राज्यों में 2.29 करोड़ वोटर कम हुए

नयी दिल्ली। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदाताओं की संख्या में 13.24 प्रतिशत तक की कमी आई है। निर्वाचन आयोग की ओर से सार्वजनिक किए गए आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। इन पांच राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। हाल में निर्वाचन आयोग और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की ओर से सार्वजनिक किए गए आंकड़ों के अनुसार, इन पांच राज्यों में मतदाताओं की संख्या एसआईआर से पहले लगभग 18.71 करोड़ थी, जो घटकर 16.43 करोड़ रह गई। इस तरह कुल मिलाकर करीब 2.29 करोड़ मतदाताओं की कमी आई, जो लगभग 12.2 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या एसआईआर से पहले 15.44 करोड़ थी, जो मसौदा मतदाता सूची में घटकर 12.56 करोड़ रह गई और अंतिम मतदाता सूची में बढ़कर 13.40 करोड़ हो गई। इस तरह मतदाताओं की शुद्ध संख्या में करीब 2.04 करोड़ यानी 13.24 प्रतिशत की कमी आयी। पंजाब में तीसरे चरण में एसआईआर कराया गया था। यहां मतदाताओं की संख्या 2.15 करोड़ से घटकर मसौदा सूची में 1.94 करोड़ रह गई और अंतिम सूची में बढ़कर 2.01 करोड़ हो गई। उत्तराखंड में मतदाताओं की संख्या 0.80 करोड़ से घटकर 0.71 करोड़ रह गई और नाम फिर से जोड़ने के बाद अंतत: 0.72 करोड़ हो गई।



बरेली : थाना प्रभारी समेत तीन दरोगा निलंबित

बरेली (एजेंसी)। बरेली में जनसुनवाई में लापरवाही और पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई न करना सीबीगंज थाना पुलिस को भारी पड़ गया। सिर में गंभीर चोट होने के बावजूद पीड़िता की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज न करने के मामले में एसएसपी अनुराग आर्य ने सीबीगंज थानाध्यक्ष समेत तीन दरोगाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

एक लाख रिश्वत लेते प्रदूषण नियंत्रण बोर्डका जेई पकड़ाया

बांदा (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में तैनात अवर अभियंता (जेई) सलमान को विजिलेंस टीम ने एक लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ लिया। आरोपी मूलरूप से मेरठ जिले का निवासी है और बांदा में आवास विकास कॉलोनी स्थित एलआईसी बिल्डिंग के पीछे रहता है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला : सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर किया निबटारा

निचली अदालत को कानून के अनुसार कारवाई करने का निर्देश



नयी दिल्ली (आससे.)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले में दायर याचिकाओं का निपटारा कर दिया। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस बयान को रिकॉर्ड पर लिया, जिसमें बताया गया कि विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मामले में आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। शीर्ष अदालत ने निचली अदालत को कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया।प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि एसआईटी की जांच में चढ़ावे की रकम की गिनती के दौरान चोरी होने की बात सामने आई है। कुछ आरोपियों ने चोरी की रकम से संपत्तियां खरीदीं, जबकि कुछ ने धनराशि बैंक खातों में जमा कर रखी है।पीठ ने याचिकाकर्ताओं को इस मामले की सुनवाई के दौरान अयोध्या की स्थानीय अदालत की सहायता करने की अनुमति भी दी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।



बंधुआ मजदूरी पर रोक सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रह सकती-सुप्रीम कोर्ट

पुनर्वास योजना में प्रस्तावित बदलावों पर तीन महीने में लें फैसला

नयी दिल्ली। बंधुआ मजदूरी से मुक्ति मिलने के बाद भी मजदूरों को अगर आर्थिक मदद और रोजगार का सहारा नहीं मिलता है तो वे दोबारा शोषण के जाल में फंस सकते हैं। इसी चिंता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बंधुआ मजदूरी खत्म करने से जुड़े कानून और पुनर्वास योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि संविधान में बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाने का प्रावधान सिर्फ कागजों पर लिखी बात बनकर नहीं रह सकता। मजदूरों को शोषण से मुक्त कराना ही सरकार की जिम्मेदारी पूरी होने के लिए काफी नहीं है, बल्कि उन्हें सम्मान से जीवन जीने के लिए जरूरी मदद भी देनी होगी। अदालत ने केंद्र को छह महीने के भीतर इस संबंध में एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने बंधुआ मजदूरी व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 और उससे जुड़ी पुनर्वास योजना को लागू करने के लिए कई निर्देश जारी किए। अदालत दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इन याचिकाओं में बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए गए लोगों को तुरंत आर्थिक सहायता देने में देरी और उनकी पहचान, रिहाई तथा पुनर्वास की व्यवस्था में कमियों का मुद्दा उठाया गया था। पीठ ने कहा कि बंधुआ मजदूरी से मुक्ति, पहचान और पुनर्वास एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी मजदूर को आजाद कराने के बाद खत्म नहीं होती। संविधान के अनुच्छेद 21 और 23 के तहत सम्मानजनक जीवन और शोषण के खिलाफ अधिकार सुनिश्चित करना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए गए व्यक्ति को रिहाई प्रमाणपत्र जारी होने के बाद आमतौर पर सात दिनों के भीतर तत्काल आर्थिक सहायता मिल जानी चाहिए।

